प्रेषक,

एम0एच0 खान, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 🤊 मार्च, 2013

विषय: नगरपालिका परिषद, पौड़ी के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वीकृत बस स्टेशन निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

जपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 2320/V-श0वि-06-210(सा0)/05टी०सी०, दिनांक 17.07. 2006 तथा शासनादेश संख्याः 1127/IV(2)-श0वि0-12-210(सा0)/05, दिनांक 04.10.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासनादेश संख्याः 2320, दिनांक 17.07.2006 द्वारा नगरपालिका परिषद, पौड़ी के अन्तर्गत बस स्टेशन के नवीनीकरण हेतु ₹ 452.09 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी थी। तत्क्रम में आपके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार उपर्युक्तानुसार निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष ₹ 226.05 लाख की धनराशि आहरित कर ड्राफ्ट् सं० 245660, दिनांक 14.08.2006 के माध्यम से नगरपालिका परिषद, पौड़ी को उपलब्ध करायी गयी थी।

उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 1127, दिनांक 04.10.2012 द्वारा बस स्टेशन निर्माण कार्य हेतु ₹ 30.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार वर्तमान तक कुल ₹ 256.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और ₹ 196.04 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु अवशेष है।

- 2— इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पौड़ी के पत्र संख्या 854 / न0पा0प0 / अवस्थापना / 2012—13, दिनांक 15.12.2012 के माध्यम से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, पौड़ी के अन्तर्गत बस स्टेशन के नवीनीकरण हेतु अवशेष सम्पूर्ण धनराशि ₹ 196.04 लाख (रूपये एक करोड़ िक्यानवे लाख चार हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—
 - उक्त धनराशि ₹ 196.04 लाख (रूपये एक करोड़ छियानवे लाख चार हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्बंधित कार्यदायी संस्था को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2. शासनादेश संख्या 2320 / V—श0वि—06—210(सा0) / 05टी०सी०, दिनांक 17.07.2006 तथा शासनादेश संख्याः 1127 / IV(2)—श0वि0—12—210(सा0) / 05, दिनांक 04.10.2012 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

 सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अविध के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

4. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

5. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिंग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही

वहन किया जायेगा।

सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी

पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- 10. उक्त धनराशि का दिनांक 31-3-2013 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- 11. उपरोक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेंगा। जिसके साथ अद्यतन तिथि तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13, के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डी को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 126.04 लाख एवं अनुदान सं0-30 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-42-अन्य व्यय' के नामे ₹ 60.00 लाख एवं अनुदान सं0-31 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत— 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामे ₹ 10.00 लाख डाला जाएगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०— 1130/xxvII(2)/2012, दिनांक— 26 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई०डी०—S..... के अधीन निर्गत किये जा रहे

(एम०एच० खान) सचिव।

60 (1)/10(2)-शा0वि0-2013, तद्दिनांक। प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून। 1.

महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।

निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी। 3.

निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन। 4.

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी। जिलाधिकारी, पौड़ी। 5.

6.

वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून। 7.

वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

निदेशक, एन0आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।

अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पौड़ी। 10.

बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून। 11.

गार्ड बुक । 12.

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र) उप सचिव।